

भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 645  
दिनांक 28 नवम्बर, 2024

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग

†645. श्री अबू ताहेर खान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, और
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

सरकार, उपभोक्ताओं के लिए यथोचित और तर्कसंगत मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में क्रमशः कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है, जो उपभोक्ताओं को पूर्णतः प्रदान की गई थी जिसके परिणामस्वरूप घरेलू पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य क्रमशः 110.04 रुपए प्रति लीटर और 98.42 रुपए प्रति लीटर से घटकर नवंबर 2021 में 94.77 रुपए प्रति लीटर और 87.67 रुपए प्रति लीटर हो गए (दिनांक 18.11.2024 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में मूल्य)। किंतु राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत पहुँचाने के निमित्त राज्य वैट की दरों को कम कर दिया था। मार्च, 2024 में ओएमसीज ने भी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी।

भारत सरकार ने आम नागरिकों को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कज्जे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, पेट्रोलियम उत्पादों के नियंत्रण पर अप्रत्याशित कर, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल हैं।

हाल ही में पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इससे राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के रूप में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेट (पीओएल) डिपो से दूर रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के अंतर को भी कम कर दिया है।

\*\*\*\*\*